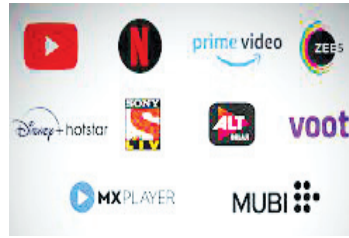


For Your
Information...Comparison
of top OTT
players
(Jun'21)

Netflix - 209 Million subscribers
Prime - 175 Million subscribers
Disney - 116M Million Susbcribers
Hulu VOD - 39 Million subscribers
ESPN - 15 Million Susbcribers
Disney+Hulu+ES PN - 170 million subscribers

विचार सागर

“यदि कोई व्यक्ति चार वेदों का अर्थ भी नहीं जानता हो पर यदि वह समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी का मर्म जानता हो तो विश्वत ही उसका जीवन सार्थक है।”

- पी.सी. वर्मा

“प्रोत्साहन भरा एक शब्द भी रूपांतरण का सामर्थ्य रखता है।”

- के.आर. कमलेश

Thoughts of the time

We do not quite forgive a giver. The hand that feeds us is in some danger of being bitten.

- Ralph Waldo Emerson

Who you spend time with is who you become.

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

खावे मांटी तै अर गीत गावे वीरे रा खाये खसम का और गीत गाये भाई का

■ खाये किसी का और गुणगान करे किसी का।

■ जिस नामसमझ व्यक्ति को कुतज्ञता प्रकट करने का ही सलीका न हो।

- स्व. विजय दान देथा

साधार : रूपयान संस्थान, बीरहटा

बाजार

Index/Commodity	IIP	Chg. (points)
BSE Sensesx	58,279.48	-17.43
NSE Nifty	17,362.10	-15.7
MCC Comdex	11360.99	-56.01
NCDEX Agrindex	1668.25	23.55
Gold(MC.Rs/10gm)	47,341	-61
Silver(MC.Rs/kg)	64,721	-577
US Dollar(in Rs.)	73.47	0.405
Gold(S/ounce)	1,814.80	-18.75
Silver(S/ounce)	24.438	-0.36
Crude Oil(\$/barrel)	67.97	-1.31
London Brent Crude (\$/barrel)	71.44	-0.78
Copper(\$/Ton)	4,2763	-0.0577
Aluminium(\$/Ton)	2,761.50	-9.5
Zinc(\$/Ton)	3,028.25	16
Lead(\$/Ton)	2,274.50	2
Nickel(\$/Ton)	19,495.00	-127.5

Rates as of 6.30 pm on 7 September 2021

बुधवार के चौघड़िए

राज्य	समय	व्यक्ति
प्रतः 6.13 से 7.46	लाभ	
7.46 से 9.19	अमृत काल	
9.19 से 10.51	शुभ	
10.51 से 12.24	रोग	
12.24 से 1.57	उद्वेग	
1.57 से 3.30	चर	
3.30 से 5.03	लाभ	
5.03 से सूर्यास्त 6.36	उद्वेग	
रात्रि 6.36 से 8.02	शुभ	
8.02 से 9.30	शुभ	
9.30 से 10.58	अमृत	

स्कूल खुलने से यूनिफॉर्म कपड़े में लौटी रौनक

भीलवाड़ा/नि.सं। कोरोना क्राइसिस शुरू होने के करीब डेढ़ साल बाद वस्त्रनगरी में स्कूल यूनिफॉर्म कपड़े की मांग आना शुरू हो गई है। स्कूल-कॉलेज खुलने से पिछले 10 दिनों में ही कपड़ा उत्पादकों के गोदामों में डेढ़ वर्ष से डम्प पड़े स्टॉक का करीब 30 से 35 प्रतिशत कपड़ा देश की विभिन्न मंडियों में डिस्पेंस हो गया है। कपड़ा उत्पादकों के मुताबिक स्कूल खुलने से बाजार में अचानक मांग बढ़ गई है। इन दिनों स्कूलों की नई ड्रेस खरीदना भी शुरू हो गया है।

पूछ-परख हुई शुरू : पिछले एक पखवाड़े से देश की कई कपड़ा मंडियों में काम-काज होने लगा है। इन दिनों स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े की पूछ परख शुरू हो गई है। कपड़ा उत्पादक पहले अपने गोदामों में रखे माल को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाजार में मांग को देखते हुए कपड़ा उत्पादकों ने नई प्लानिंग शुरू कर दी है, जिससे जॉब पर कपड़ा तैयार होने वाले खातों पर दबाव आना शुरू हो गया है। यही कारण है कि लूमों पर कपड़ा उत्पादन का कार्य बढ़ने लगा है।

ग्रे धागे में आई तेजी : आने वाले दिनों में सभी प्रकार के कपड़ों की मांग में तेजी शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। शादियों में लोगों की आवाजाही बढ़ी है। आगामी जनवरी तक तीज त्यौहारों के कई कार्यक्रम होने वाले हैं, वहीं दिसम्बर में न्यू ईयर पर यूरोप के बाजारों से कपड़े की बड़ी मांग की उम्मीद लगाई जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट का वोल्यूम बढ़ने



की संभावना है। केरल के अलावा बाकी राज्यों में मांग बढ़ने की संभावना बनी हुई है। इन कारणों से ग्रे धागे में तेजी आ गई है, वहीं मांग बढ़ने से आपूर्ति में विलम्ब होने लगा है।

कपड़े की कीमतों में तेजी के संकेत : कपड़ा उत्पादन और प्रोसेस के काम में आने वाले रॉ मैटेरियल कोयला, डाइज-केमिकल और विद्युत दरों के जिस तेजी से मूल्य बढ़ रहे हैं, उसका सीधा असर कपड़े की उत्पादन लागत पर पड़ेगा। इसका असर नये कपड़े के उत्पादन पर आना शुरू हो जाएगा। जिस तेजी से डाइज-केमिकल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं उसके साथ ही डाइज धागों के मूल्यों में तेजी के संकेत आने शुरू हो गए हैं।

कई रंगों के धागों की सोरटेज : कपड़ा बाजार के लम्बे समय के बाद खुलने से कई प्रकार के रंगों के धागों की उपलब्धता में परेशानी आ रही है। कई रंगों के धागों की सोरटेज बनी हुई है। इस बारे में

धागा उत्पादकों का कहना है कि जल्द ही यह कमी दूर हो जाएगी। बाजार की मांग के अनुरूप विभिन्न रंगों के धागों का उत्पादन बढ़ने लगेगा।

लुधियाना सहित सभी कपड़ा उत्पादक केन्द्रों से धागे की मांग आना शुरू : धागा उत्पादन की दृष्टि से भीलवाड़ा देश का बड़ा केन्द्र है। यहां सभी प्रकार के धागों का उत्पादन होता है। कपड़ा बनाने का कार्य सभी क्षेत्र में शुरू होने से धागा उत्पादन करने वाली मिलों में दबाव आना शुरू हो गया है। लुधियाना विशेष प्रकार के कपड़ों के उत्पादन का बड़ा केन्द्र है। यहां बाजार सामान्य होने से विशेष प्रकार के धागों की मांग बढ़ गई है।

नांगातंगी से मिलेगी निजात : भीलवाड़ा के कपड़ा बाजार में नकद की तुलना में उधारी पर अधिक बिजनेस होने के कारण कपड़ा बाजार के नहीं चलने के कारण लम्बे समय से नांगातंगी बनी हुई है, लेकिन बाजार के चलने के बाद नया माल मंगवाने से पहले पुरानी बकाया राशि के भुगतान के बाद ही नया माल भेजने का प्रचलन है। लम्बे समय से चल रही उधारी का पैसा आने से बाजार में नांगातंगी की स्थिति से निजात मिलेगी।

तीसरी लहर का डर हुआ कम : सर्दियों के लिए ड्रेस की तैयारियां अगस्त से शुरू हो जाती हैं। वर्तमान में सरकारों की तैयारी को देखते कोरोना की तीसरी लहर का डर कम होने लगा है। जिससे के कारण कारोबारियों ने काम शुरू कर दिया है।

‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत राज्य में वाणिज्य सप्ताह का आयोजन 20 से

जयपुर/का.सं। राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत 21 और 22 सितंबर को जयपुर में होने वाले दो दिवसीय राज्य स्तरीय ‘वाणिज्य उत्सव’ से होगी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को लिखे पत्र के अनुसार राजस्थान के सभी जिलों में 24 से 26 सितंबर के मध्य एक दिवसीय निर्यात सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर और जोधपुर में ‘मेगा एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्लेव’ होंगे। साथ ही राज्य के अन्य जिलों में एक दिवसीय ‘एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्लेव’ का आयोजन किया जाएगा।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त अर्चना सिंह ने बताया कि निर्यात गतिविधियों को जिला स्तर तक पहुंचाने के लिए मिशन निर्यातक बनो

जयपुर में 21 व 22 सितंबर को होगा राज्य स्तरीय वाणिज्य उत्सव

संचालित किया जा रहा है। ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत आयोजित होने वाले वाणिज्य सप्ताह के माध्यम से निर्यात से जुड़े सभी हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर समन्वय स्थापित किया जाएगा। वाणिज्य सप्ताह के तहत होने वाले एक दिवसीय ‘एक्सपोर्टर्स कॉन्फ्लेव’ का आयोजन अलवर, झुंझु, सीकर, दौसा, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर, नागौर और जैसलमेर में 24 सितंबर को होगा। भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सर्वाइ माधोपुर, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा में 25 सितंबर और बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में होगा।

बिना टिकट, बिना मास्क यात्रा करने वालों से 46 लाख रुपए वसूले

जोधपुर/नि.सं। जोधपुर रेल मण्डल पर जांच के दौरान बिना टिकट यात्रा करने, बिना मास्क व अन्य अनाधिकृत क्लॉकों के लिए अगस्त में 11362 यात्रियों से 46 लाख 75 हजार 565 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए। मण्डल रेल प्रबन्धक गीतिका पाण्डेय के निर्देशन में रेलवे राजस्व प्राप्त करने, कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क लगाने के नियम की पालना करने, रेलवे परिसर को स्वच्छ बनाए रखने व बिना बुक कराए निर्धारित मात्रा से अधिक सामान लेकर यात्रा करने आदि के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक धीरुमल ने बताया कि जोधपुर मण्डल पर अगस्त में बिना टिकट व अनाधिकृत यात्रा के 9856 मामलों में 20 लाख 12 हजार 53 रुपए किराया राशि तथा 24 लाख 94 हजार 542 रुपए सहित कुल 45 लाख 6 हजार 595 रुपए वसूले गए। कोरोना गार्डब्लाइंड के अनुसार 1293 यात्रियों को बिना मास्क पाए जाने पर उनसे 1 लाख 43 हजार 100 रुपए वसूले गए। मण्डल प्रवक्ता गोपाल शर्मा ने बताया कि इसके अलावा 185 यात्रियों से गंदगी फैलाने, 27 यात्रियों से प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान करने तथा एक यात्री से निर्धारित मात्रा से अधिक सामान ले जाने के लिये 25 हजार 870 रुपए जुर्माना वसूला गया।

नेशनल • इंटरनेशनल

टेक्निकल टैक्सटाइल, मेन-मैड फाइबर के लिये पीएलआई योजना को मिल सकती है मंत्रिमंडल की मंजूरी

नयी दिल्ली/एजेंसी

केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को 10,683 करोड़ रुपये व्यय के साथ टेक्निकल टैक्सटाइल और मेन-मैड रेशे (एएमएमएफ) के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे सकता है। इस पहल का मकसद घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उसने कहा कि प्रस्ताव बुधवार को विचार के लिये मंत्रिमंडल के समक्ष आ सकता है। मंत्रिमंडल इससे पहले देश में

विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिये पीएलआई योजना को मंजूरी दे चुका है। अधिकारी के अनुसार मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कपड़ा मंत्रालय संबंधित क्षेत्रों के लिये विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

योजना का मकसद भारत में संबंधित क्षेत्रों में समस्याओं को दूर कर, पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त कर तथा दक्षता सुनिश्चित कर विनिर्माण को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसे भारत में अनुकूल परिवेश बनाने और देश

को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के उद्देश्य के साथ तैयार किया गया है।

इस योजना से वैश्विक निवेश आकर्षित होने, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होने और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। यह योजना घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रमुख इकाई बनने में भी मदद करेगी। भारत के मानव निर्मित रेशे से बने कपड़ों का निर्यात उसके कुल परिधान निर्यात का केवल 10 प्रतिशत है। यह 2019-20 में लगभग 16 अरब डालर था।

सेबी ने धोखाधड़ी से कारोबार करने पर 85 व्यक्तियों, संस्थाओं पर पूंजी बाजार में जाने से रोक लगाई

नयी दिल्ली/एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को सनराइज एशियन लिमिटेड समेत कुल 85 व्यक्तियों और संस्थाओं को कंपनी के शेयर मूल्य में हेराफेरी करने के चलते पूंजी बाजार में कारोबार करने पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी। नियामक ने अपने आदेश में सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन पांच निदेशकों को पूंजी बाजार से एक साल के लिए और 79 संबंधित इकाइयों को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रधान आयकर निदेशक (जांच), कोलकाता से मिले एक संदर्भ के आधार पर 16 अक्टूबर 2012 से 30 सितंबर 2015 की अवधि के दौरान सनराइज एशियन के शेयरों की जांच की थी। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि विलय योजना के तहत शेयरों के आवंटन के अनुसार सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन निदेशकों ने एक व्यवस्था तैयार की थी, जिसके तहत 83 संबंधित इकाइयों ने जांच अवधि के दौरान शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी, जिससे धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार (पीएफयूटीपी) मामलों का उल्लेख हुआ। नियामक ने एक अलग आदेश में कोरल हब लिमिटेड को पूंजी बाजार से तीन साल के लिए और छह व्यक्तियों को 2-3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

क्रिप्टो मुद्रा नहीं है, संपत्ति के रूप में नियमन किए जाने की जरूरत : पूर्व डिप्टी गवर्नर, आरबीआई

नयी दिल्ली/एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने मंगलवार को कहा कि ‘क्रिप्टो’ को मुद्रा नहीं बल्कि एक अलग संपत्ति वर्ग को तरह माना जाना चाहिए और उसी रूप में उसका नियमन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर की सरकारों को आभासी मुद्राओं से जुड़ी अवैध गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। गांधी ने कहा कि वर्षों की बहस के बाद लोग पूरी तरह से समझ गए हैं कि क्रिप्टो मुद्रा नहीं हो सकती, क्योंकि मुद्रा का मूल तत्व है कि यह कानूनी रूप से वैध होनी चाहिए, जो इसके मामले में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी किसी अन्य व्यक्ति को क्रिप्टो स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह कानूनी रूप से वैध नहीं है। गांधी ने कहा कि कई नीति निर्माताओं के बीच इसको लेकर आम सहमति है कि इसे एक संपत्ति के रूप में समझा जाना चाहिए, न कि एक मुद्रा के रूप में। इसे एक भुगतान साधन के रूप में या एक वित्तीय साधन के रूप में भी नहीं स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई स्पष्ट जारिकर्ता नहीं है। उन्होंने भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ (आईएमएआई) और ब्लॉकचैन एवं क्रिप्टो संपत्ति परिषद (बीएसीसी) द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में कहा, “इसलिए एक बार जब हम समझ जाते हैं और इस बात की स्वीकृति मिल जाती है कि यह एक संपत्ति है (मुद्रा नहीं), तो इसका विनियमन करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।”

उन्होंने आशंका जताई कि नियमन के अभाव में इस आभासी संपत्ति का आपराधिक गतिविधि के लिए उपयोग हो सकता है और इसका संकेत देने वाले कई उदाहरण हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि क्रिप्टो मुद्रा के संबंध में प्रस्तावित कानून केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष लंबित है। क्रिप्टो मुद्रा पर अंतर-मंत्रालयी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भारत में राज्य द्वारा जारी किसी भी आभासी मुद्रा को छोड़कर, सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इस बीच आरबीआई ने बाजार में आ चुकी क्रिप्टो मुद्रा पर चिंता जताई है और उसने सरकार को भी इससे अवगत करा दिया है।

बीसीएम ग्रुप के नए प्रोजेक्ट ‘मा बीसीएम टाऊनशिप’ का शुभारंभ

पाली/नि.सं। क्षेत्र की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी बीसीएम प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड जो पिछले सात वर्षों से आर्थिक रूप से मध्यम वर्ग को न्यूनतम दर पर फ्लैट एवं भूखंड उपलब्ध करने में कार्यरत है। कंपनी आज लगभग संपूर्ण संभाव्य स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रही है। बीसीएम ग्रुप ने नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत ‘मा बीसीएम टाऊनशिप’ के नाम से नई आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ किया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक मगराज जैन ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पुलिस लाइन रोड स्थित जगदंबा नगर बीसीएम आशियाना के समीप स्थित है। इस परियोजना में 56 आवासीय भूखंड एवं 9 व्यावसायिक भूखंड ग्राहकों को उचित दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निदेशक राहुल जैन व आशीष संकलेचा ने बताया कि इस भूखंड परियोजना में 30 और 40 फीट चौड़ी सड़कें, बिजली के खंभे एवं शुद्ध पर्यावरण के लिए बगीचे की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कारोबारियों ने किया औद्योगिक व व्यापारिक विकास पर मंथन

बीकानेर/नि.सं। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की कार्यकारिणी बैठक अध्यक्ष जुगल राठी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में व्यापार उद्योग सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। विशेषकर बीकानेर में लंबे समय से ड्राईपोर्ट की स्थापना न होना, कोटा की तर्ज पर बीकानेर में भी हवाई सेवा विस्तार को लेकर 58.18 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध करवाने, छोटे व्यापारियों व उद्यमियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र राज्य सरकार व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की जाएगी। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल का मुख्य ध्येय बीकानेर के औद्योगिक व व्यापारिक विकास के आड़े आ रही समस्याओं से केंद्र व राज्य सरकार को अवगत करवाना रहेगा ताकि बीकानेर भी एक विकसित शहर के रूप में अपनी पहचान बनाए रख सकेगा। इस अवसर पर संरक्षक परिषद अध्यक्ष अंतर्वीर जैन, सचिव चंपकमल सुराणा, सचिव वीरेंद्र किराडू, द्वारकाप्रसाद पचीसिया आदि शामिल हुए।

उद्योगों में इनोवेशन व तकनीकी कौशल में वृद्धि को मिलेगा नया आयाम

जोधपुर/नि.सं। आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. शान्तनु चौधरी और जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (जेआईए) के अध्यक्ष एन.के. जैन द्वारा एम्स जोधपुर में आयोजित एमओयू समारोह में विज्ञान और बदलती तकनीक के बारे में जागरूकता के लिए अनुसंधान और विकास में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य तकनीकी समस्याओं को हल करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर आईआईटी जोधपुर द्वारा जोधपुर की अग्रणीय शोध संस्थानों जैसे एम्स, डीआरडीओ, इसरो, डॉ. एस एन मेडिकल कॉलेज इत्यादि के साथ भी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। प्रो. शान्तनु चौधरी ने कहा कि यह समय है कि सभी अकादमिक संस्थान उद्योग के साथ एक मंच पर आये हैं और समाज के लाभ के लिए तेजी से बदलती तकनीक पर विचार करने के लिए हाथ से हाथ मिलाकर काम करना शुरू करते हैं।

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम उन्नति पाटनी से बदलकर उन्नति दीवान रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

पता: 158, वसुंधरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर-302018 (राज.)

INANI MARBLES & INDUSTRIES LIMITED

(CIN: L14101RJ1994PLC008930)
Registered Office: Araji No. 1312, Udaipur-Bhilwara Highway, Near Mataji Ki Pandoli Chittorgarh, Rajasthan-312001, E-mail: inanimarble@gmail.com Website: www.inanimarbles.com

NOTICE CONCERNING THE 27th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF INANI MARBLES & INDUSTRIES LIMITED AND E-VOTING INFORMATION, BOOK CLOSURE INTIMATION

Notice is hereby given that the 27th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on Thursday, September 30, 2021 at 03:00 P.M. IST through video conferencing ("VC") Other Audio Visual Means(OAVM) in compliance with General Circular number 20/2020, 14/2020, 17/2020, 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that will be set forth in the Notice of Meeting.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for fiscal 2021 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Ankit Consultancy Private Limited at ankit_4321@yahoo.com. The Notice of the 27th Annual General Meeting and Annual Report for fiscal 2021 will also be made available on the Company's Website at www.inanimarbles.com, stock exchange website and on the CDSL's website at www.evotingindia.com. Members can attend and participate at the AGM through VC/OAVM only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members attending through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (as amended) (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company is pleased to provide its shareholders the facility to cast their vote on the resolutions set forth in the Notice through electronic voting system ("REMOTE E-VOTING") of Central Depository Service (India) Limited (CDSL).

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 (as amended), the Company further informs all Members that:

- The Business set out in the Notice may be voted electronically.
- The date of Completion of sending of Notice on 07th September, 2021
- The Voting rights of the Members shall be in proportion to the Equity Shares held by them in the paid up Equity Shares Capital of the Company as on Cut-off date i.e. September 23, 2021.
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting is September 23, 2021. A person whose name is recorded in the Depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- Any Person, who become a member of the Company after dispatch of e-AGM Notice, and is a member as on the cut-off date for e-voting, i.e., September 23, 2021, such person may obtain the user id and password by sending a request to evoting@cdslindia.com by mentioning his / her DP ID and Client ID.
- The remote e-voting period commences on Monday, September 27, 2021 (9:00 a.m.) and ends on Wednesday, September 29, 2021 (5:00 p.m.).
- The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 29, 2021. The facility for e-voting shall also be made available at the time of AGM and Members attending the meeting who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Detailed procedure for remote e-voting at the AGM are provided in the Notice.
- The Notice of AGM, together with Explanatory statement, Remote E-voting instructions and the process of e-mail registration of non-registered members to avail Notice of AGM & Procedure for "Remote E-voting" in terms of MCA Circulars is available on the Company Website -www.inanimarbles.com and on CDSL website www.evotingindia.com.
- In light of the MCA Circulars, Members who have not registered their email address may get their email address registered by sending an email to the Company's Share Transfer Agent at ankit_4321@yahoo.com, member(s) may also intimate the same to the Company by writing an email at inanimarble@gmail.com
- Members are hereby requested to register their email addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants and in respect of physical holdings, with the Company's Share Transfer Agent i.e. Ankit Consultancy Private Limited.
- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, rule 1 of the companies (management and administration) rule 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, the Register of Member and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Friday, 24th September 2021 to Thursday, 30th September 2021, (Both days inclusive) for the purpose of 27th AGM and payment of dividend, if approved in the said AGM.

In case of any queries or grievances regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual which is available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com, helpdesk number-1800-200-5533.

For Inani Marbles & Industries Limited
Sd/- Madhu Bala Sharma
Company Secretary

Date: 07.09.2021
Place: Chittorgarh

Lower Import Duty Likely on Edible Oils to Rein in Prices

Effective duty may be brought down on crude and refined vegetable oils

By **Arpita Bhatnagar** in New Delhi

New Delhi: India is likely to lower the effective import duty on edible oils to provide some relief to consumers from rising prices. The government is considering reducing the effective import duty on crude palm oil from 10% to 5% and refined palm oil from 10% to 5% and refined sunflower oil from 10% to 5%.

This is a crucial move to food inflation as a step to ensure that prices during the festive season remain under control, said an official in the Ministry of Commerce.

The move comes in the wake of prices of refined, vegetable, soya and palm oil having increased about 50% while that of sunflower oil has risen 40% over the last year. Crude and refined palm oil has risen 100% and 120% respectively.

On the Boil

Duty on crude palm oil to be cut from 10% to 5%
 Refined palm oil to be cut from 10% to 5%
 Sunflower oil to be cut from 10% to 5%

Inflation in food & oils was 32.5% in July vs 6.6% in Jan

India exports nearly no imports for edible oils

India is the largest importer of vegetable oils and about 80% of the demand is met through imports. New Delhi has palm oil from Indonesia and Malaysia while soya oil and sunflower oil are imported from Argentina, Brazil, US, India and Russia.

While there is a shortage of domestic supply on imports, there is also an over-reliance on imports. In the process of stabilising prices, the government is likely to reduce the effective import duty on crude palm oil from 10% to 5% and refined palm oil from 10% to 5% and sunflower oil from 10% to 5%.

Guidelines to Authenticate E-records Eased

By **Arpita Bhatnagar** in New Delhi

New Delhi: The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has issued guidelines to authenticate e-records. The guidelines are aimed at providing a clear framework for the authentication of e-records. The guidelines are aimed at providing a clear framework for the authentication of e-records.

The guidelines are aimed at providing a clear framework for the authentication of e-records. The guidelines are aimed at providing a clear framework for the authentication of e-records.

Fitch Retains Sovereign Rating for India at BBB-

New Delhi: Fitch Ratings has retained India's sovereign rating at BBB- with a 'stable' outlook. The agency noted that the Indian government's efforts to manage the economy and control inflation are positive. The agency also noted that the Indian government's efforts to manage the economy and control inflation are positive.

The agency also noted that the Indian government's efforts to manage the economy and control inflation are positive. The agency also noted that the Indian government's efforts to manage the economy and control inflation are positive.

Norms Update in the Works for Syndicated Loans Above ₹2k cr

By **Shreya Tiwari** in New Delhi

New Delhi: The Reserve Bank of India (RBI) is in the process of updating the norms for syndicated loans above ₹2k crore. The RBI is in the process of updating the norms for syndicated loans above ₹2k crore.

The RBI is in the process of updating the norms for syndicated loans above ₹2k crore. The RBI is in the process of updating the norms for syndicated loans above ₹2k crore.

Paradip Port Trust

Paradip Port Trust is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The trust is responsible for the development and maintenance of the Paradip Port.

The trust is responsible for the development and maintenance of the Paradip Port. The trust is responsible for the development and maintenance of the Paradip Port.

INANI MARBLES & INDUSTRIES LIMITED

INANI MARBLES & INDUSTRIES LIMITED is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The company is engaged in the business of marble and granite.

The company is engaged in the business of marble and granite. The company is engaged in the business of marble and granite.

HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The company is engaged in the business of aircraft manufacturing.

The company is engaged in the business of aircraft manufacturing. The company is engaged in the business of aircraft manufacturing.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

PARADIP PORT TRUST

Paradip Port Trust is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The trust is responsible for the development and maintenance of the Paradip Port.

The trust is responsible for the development and maintenance of the Paradip Port. The trust is responsible for the development and maintenance of the Paradip Port.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

GET FREE RENT INSURANCE PLUS CASHBACK & OTHER BENEFITS WORTH ₹23,000/-

When you pay rent using your credit card on mb



Log on to magibricks.com/loyrent

Magibricks is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The company is engaged in the business of insurance.

The company is engaged in the business of insurance. The company is engaged in the business of insurance.

DOLAT INVESTMENTS LIMITED

Dolat Investments Limited is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The company is engaged in the business of investment.

The company is engaged in the business of investment. The company is engaged in the business of investment.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

DOLAT INVESTMENTS LIMITED

Dolat Investments Limited is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The company is engaged in the business of investment.

The company is engaged in the business of investment. The company is engaged in the business of investment.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

DOLAT INVESTMENTS LIMITED

Dolat Investments Limited is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The company is engaged in the business of investment.

The company is engaged in the business of investment. The company is engaged in the business of investment.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

DOLAT INVESTMENTS LIMITED

Dolat Investments Limited is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The company is engaged in the business of investment.

The company is engaged in the business of investment. The company is engaged in the business of investment.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.

UCC BANK

UCC Bank is a public sector enterprise under the administrative control of the Government of India. The bank is engaged in the business of banking.

The bank is engaged in the business of banking. The bank is engaged in the business of banking.